

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1046
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जननी सुरक्षा योजना

1046. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए "जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)" क्रियान्वित की जा रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और वर्ष 2020 से 2024 तक हरियाणा के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की वर्षबार और जिला/ब्लॉक-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत भुगतान में देरी, अभिलेखों में विसंगति या पात्र महिलाओं को लाभ न मिलने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;
- (घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों की जाँच हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और उनमें सुधार के लिए क्या व्यवस्था की गई है;
- (ङ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के वितरण को पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाने के लिए भविष्य में कोई नई पहल करने की योजना बना रही है; और
- (च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सोनीपत और जींद, दो जिले शामिल हैं। जैसा कि हरियाणा राज्य द्वारा साझा किया गया है, वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक इस योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं की संख्या का जिला-वार विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

जिला	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सोनीपत	2078	1326	974	1230	1353	1634
जींद	1826	853	997	2233	1630	1782
कुल	3,904	2,179	1,971	3,463	2,983	3,416

(ग) और (घ): हरियाणा राज्य ने रिपोर्ट किया है कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, सोनीपत लोकसभा निर्वाचिक क्षेत्र में जेएसवाई योजना के तहत, भुगतान में देरी, रिकॉर्ड में विसंगति या पात्र महिलाओं को लाभ नहीं मिलने से संबन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च): जेएसवाई के तहत भुगतान में सुधार के लिए, राज्य द्वारा बताया गया है कि निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- जेएसवाई लाभ का दावा करने हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों के ब्यौरे के साथ एक मानक "वन पेज जेएसवाई फॉर्म" लागू किया गया है; जिसे सभी जिलों में लागू किया गया है;
- अप्रैल 2025 से जेएसवाई लाभार्थियों के खातों में पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध भुगतान के लिए एस एन ए स्पर्श राज्य में लागू किया गया है, और
- जे. एस. वाई. योजना की नियमित निगरानी राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी. सी.), त्रैमासिक जे. एस. वाई. रिपोर्ट तथा सिस्टमैटिक असेसमैट एंड रिजीलियेंट ट्रांसफारमेशन इन हेल्थ एंड नॉलेज (सार्थक) कार्यक्रम के तहत राज्य टीमों द्वारा किए गए सहायक पर्यवेक्षण दौरों के दौरान भी की जाती है।

इस योजना के तहत लाभ के वितरण को पारदर्शी, डिजिटल और समय पर करने के लिए इस योजना को डीबीटी योजना के रूप में अधिसूचित किया गया है और राज्य द्वारा भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाता है।
